

ECONOMICS

PROF - N. Ram

Assistant Professor

R.B.C.R College

Maharashtra (SIwan)

TDC Part I Economics (Hons.)

Paper II Indian Economy

Topic - Is India over populated

वहा भारत में जनाधिकरण है ?

प्रश्न क्या भारत में जनाधिकरण है ? अपने उत्तर के फारण सहित ज्ञानयामी जीजरे ?

Ans -> क्या भारत में जनाधिकरण है इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें जनाधिकरण (over population) का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। जनसंख्या का सम्बन्ध (Optimum population) यह है कि आवश्यक जनसंख्या वह है जिससे किसी देश के प्राकृतिक साधनों का समुचित रूप से उपयोग हो सके तथा प्रतिष्पत्ति आय का स्तर अधिकतम हो। यदि किसी देश की जनसंख्या आवश्यक जनसंख्या से अधिक हो तो उसे इस जनाधिकरण की स्थिति कहते हैं। ऐसी स्थिति में देश के प्राकृतिक साधनों पर जनाधिकरण की अनेक अपरिवर्तनीय असर हो जाती है। इसके फलस्वरूप उत्पादन में कमी होने लगती है तथा प्रति व्यक्ति आय (per capita income) भी घटने लगती है।

भारत में जनाधिकरण है या नहीं, यह सर्वदा एक विवाद का विषय रहा है। इस सम्बन्ध में दो परस्पर विरोधी नई दिशा जाते हैं:-

- (1) भारत में जनाधिकरण के विरोध में तक्त तथा
- (2) भारत में जनाधिकरण के पक्ष में तक्त

विषय इसका अल्पा अल्पा विस्तार द्वारा अध्ययन करेंगे

भारत में जनाधिकरण के विरोध में तक्त

सर्वप्रथम युद्ध लोग यहसे हैं जो यह कहते हैं कि भारत में जनाधिकरण की स्थिति नहीं है और वे जनाधिकरण के विरोध में तक्त हैं। 1931 की जनगणना के आसुक्त डॉ हरन, प्रो० पी० जौह दाम से तक्त कर्वे का विचार है कि भारत में जनाधिकरण नहीं है। इस भव के सर्वपक्षों को कहना है कि भारत में जनाधिकरण नहीं है वल्कि हमारे पास जो व्याधन है उसका समुचित विकास और उपयोग नहीं होने के कारण देश में गरीबी है। उनका विचार है कि वही ही अबादी देश कल्याण के लिये बाधक नहीं बल्कि सहायता है। आर्योग्य बिनोक्ति भाव ने भी कहा है कि आदमी जन्म लेने के साथ ही ही लघु और सीधे लेहराता है।

जपानिक उसके पास मुहूर्षक ही है। यदि उसे उचित साधन मिले तो वह अपना ही भरण पौष्टि नहीं कर सकता बरन् दुखरा को रिबलाने के लिए उपयोग बन सकता है। इसलिए भारत की गरीबी को मिटाने के लिए जनसंरक्षण पर नियंत्रण न कर देश के विशाल प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग करना चाहिए। इस विवार के समर्थकों ने भारत में जनाधिकरण के विरोध में निम्नलिखित तर्फ दिये हैं:-

(1) **प्रतिश्वेति आय में उत्तरान्तर वृद्धि (Gradual Rise in per capita income)** :- भारत में जनाधिकरण के विरोध में तर्फ हेतु हुए कहा जाता है कि यहाँ प्रतिश्वेति आय में उत्तरान्तर वृद्धि ही रही है। यदि जनाधिकरण होता तो ऐसा कभी नहीं होता। उदाहरण के लिए 1968 में दादाभाई नोरोजी के अनुसार भारत में प्रति श्वेति आय 20 रुपये थी, लाई कर्जन के अनुसार 1900 ई० में 33 रुपये किए जिराप के अनुसार 1911 में 49 रुपये तथा इन राष्ट्र के अनुसार 1931-32 तथा 1942-43 में क्रमशः 65 रुपये तथा 114 रुपये हो गयी। लंतव्यां प्राप्ति तथा उसके बाद भी प्रति श्वेति आय वरावर बढ़ती रही। इन्हें लंतव्यां प्रति श्वेति भारत की प्रति श्वेति आय 1947-48 में 172 रुपये थी जो बहर 1950-51 में 246 रुपये 1960-61 में 306 रुपये, 1970-71 में 633 रुपये, 1980-81 में 1630 रुपये तथा 1995-96 में 10160 रुपये तथा 2009-10 में 46,492 रुपये हो गयी। इस प्रकार प्रति श्वेति आय में उत्तरान्तर वृद्धि इस बात का सूत्र है कि भारत में जनाधिकरण की विप्रति नहीं है।

लेकिन लंतव्य में देखा जाय तो मुझ स्फीति के कारण केवल प्रति श्वेति मौद्रिक आय में वृद्धि हुई है, प्रति श्वेति लंतव्यिक आय में इन वर्षों में कोई विशेष परिवर्त्तन नहीं हुआ है अतः उपरोक्त तरफ के आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि भारत में जनाधिकरण की विप्रति नहीं है।

(2) **जनसंरक्षण का अपेक्षाकृत कम घनत्व (Comparatively Less density of population)** :- ऐसा कहा जाता है कि भारत में अन्य देशों की तुलना में जनसंरक्षण का घनत्व कम है। उदाहरण के लिए, नीदरलैंड, जापान, पश्चिमी अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि देशों की तुलना में भारत में जनसंरक्षण घनत्व कम है। अतः यहाँ जनाधिकरण की विप्रति नहीं है।

लेकिन इथान देखे की बात है कि उपरोक्त यज्ञी-देश औद्योगिक देश हैं जिनमें प्रति कर्त्तव्यालय प्रायः अधिक श्वेति व्यक्तियों का जीवन निर्वाह हो सकता है। उसकी तुलना में भारत जैसे वृक्षिकृत्यान देश के नहीं की जानी चाहिए। ऐसे कुछ धरान देश में व्यायः प्रति कर्त्तव्यालय कम जनसंरक्षण का निर्वाह हो सकता है। अतः हम अह नहीं कह सकते हैं कि पश्चिम के औद्योगिक देश की तुलना में भारत में जनसंरक्षण का घनत्व कम है, अतः यहाँ जनाधिकरण की विप्रति नहीं है।

(3) **क्षम का अभाव (Lack of labour force)** :- यहाँ कहा जाता है कि भारत में क्षम की कमी है जिससे यह कृष्ण गलत है कि भारत में

भनाधिक्य है। लेकिन यह भी तर्क गणत है। भारत में वास्तव में जन्म की कमी नहीं बरन यहाँ तो पूर्ण उपचिकता है। जन्म की कमी के कारण जनसंख्या में कमी नहीं आपितु औद्योगिक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव है।

इस प्रकार भारत में जनाधिक्य के विरोध में उपचुक्त तर्क दिये जाते हैं। लेकिन वास्तव में इन तर्कों में सत्यता नहीं है।

भारत में जनाधिक्य के पक्ष में तर्क

Arguments in favour of over-population in India

दुसरी ओर डॉ राधाकृष्णन मुख्यजी, प्री जानवन्द आदि विद्वानों का मत है कि भारत में जनाधिक्य की स्थिति है। इस मत के समर्थकों का कहना है कि भारत में माल्ट्हस (Malthus) के जनसंख्या सिफाऱन में बल्लाल गते जनाधिक्य में सभी लक्षण मौजूद हैं जैसे- जनसंख्या की कमी एवं खाद्यान जी शर्त में असंतुलन के अनेक लक्षण मौजूद हैं। इसलिये भारत में जनाधिक्य के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं।

(1) **जनसंख्या की कमी एवं खाद्यान की पूर्ति में असंतुलन :**— भारत एक कृषि ज्ञान देश है लेकिन फिर भी देशवासियों के भरण पोषण के लिये यहाँ प्रयोग्य जाता में अन्न बाज़ार नहीं होता है। इससे देश में कमबर खाद्यान का संकट बना रहता है और इसे दूर करने के लिये प्रयत्न पर्याप्त अर्थों खपत का खाद्यान विदेशी से आयात करना पड़ता है। यही की है कि देश में विगत कुछ वर्षों में खाद्यान के उत्पादन में काफी कमी हुई है। लोकेन जनसंख्या में तेजी से हुई होने के कारण ज्ञानी प्रयत्नित खाद्यान की उपलब्धि प्रायः स्थिर रही है। उदाहरण के लिये 1951 में प्रतिष्ठानित खाद्यान की उपलब्धि 304.8 ग्राम थी जो 1961 में बढ़कर 468.7 ग्राम तथा 1991 में 510 ग्राम हो गयी लेकिन 1992 में यह बढ़कर 469 ग्राम तथा 2009 में करीब 444 ग्राम हो गयी। इस प्रकार इन वर्षों में प्रति प्रयत्नित खाद्यान की उपलब्धि में प्रायः कमी ही हुई। यह वास्तव में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का सूचक है। यही जनसंख्या तेजी से नहीं बढ़ती तो खाद्यान में कुल उत्पादन में कमी होने के साथ साथ तकि प्रयत्नित खाद्यान की उपलब्धि में भी हुई होती। लेकिन सेसा नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि भारत में जनाधिक्य की स्थिति विद्यमान है।

(2) **कृषि पर जनसंख्या की अत्यधिक निर्भरता :**— भारत में कुल जनसंख्या के करीब 70 प्रतिशत लोग कृषि पर आन्ध्रित हैं। इस प्रकार कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ गया है और उत्पादन में जितनी हुई होनी प्राहित भी जितनी नहीं होती। वास्तव में कृषि के क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लग रहे हैं अपनाएं दुसरे शब्दों में कहा जाता कि कृषि में घिरी हुई बेरोजगारी (Unemployment) विद्यमान है। सेसा अनुमान लगाया जाया है कि भारत में कृषि में लोगों में से करीब

करीब 11% प्रतिवर्ष उत्पादन का घटाव हिंग भारत में भी कुछ उत्पादन जैसे कोई कमी नहीं होती। पुणे उत्सर्जना ने सूझि होने के साथ साथ प्रतिवर्षान्वयन कृषि विकास में कमी भी रखी है। उदाहरण के लिए 1931-
1932 में ब्रिटिश उपराज्यकालीन ग्रुमि 0.88 रुपये थी जो 1951-52 में 1.72 रुपये और 1969-70 में 2.42 रुपये 0.96 रुपये हो गयी है। इन वज़तों से भव साफ आहिर होता है कि भारत में जनाधिकार की दिशाति है।

(3) अपूर्णभूतीय विकास (Inadequate industrial development):— भारत में उद्योगों का विकास भी प्रभावित नहीं है जो जनाधिकार की स्थापित को प्रकट करता है। हम आनंद हैं कि औद्योगिक विकास द्वंजी निर्माण पर क्षमा द्वंजी निर्माण क्षमा (Savang) पर निर्भर करता है। लेकिन भारत में भी कुछ भी उत्पादन होता है उसका अधिकांश भाग बड़ी हुई खनसंरच्या उपभोग के भासी है जिससे क्षम बहुत कम होती है और उद्योगों का विकास नहीं हो पाता। इसमें बड़ी हुई खनसंरच्या को उद्योगों में प्रभावित नहोगा भी नहीं मिलता। अहं भारत में जनाधिकार का सूचक है।

(4) प्रतिवेदक निरोध की कमी (Lack of Prentive checks):— भारत में प्रतिवेदक निरोध की कमी अपनाया जाना; भी जनाधिकार का सूचक है। प्रतिवेदक निरोध में दूर से शादी करना, व्याहार्य लालन, अविवाहित जीवन उपर्यात करना, आत्मसंस्त तथा संतानि निरोध के कुनिम साधनों का प्रभाग करना आदि आते हैं। लेकिन भारत में गरीबी, रुद्धिवादिता, अधिक्षां आदि के कारण इन प्रतिवेदक निरोध की कमी है जिससे खनसंरच्या में तजी से सूझि हुई है और जनाधिकार की स्थापित उपन्त हो गई है।

(5) प्राकृतिक प्रकौपों का प्रभाव (Effects of Natural calamities):— मालयस ने बतलाया था कि अदि प्रतिवेदक निरोध को नहीं अपनाया जाया तो प्राकृतिक निरोध (Positive checks) बढ़ी हुई खनसंरच्या को कम करने के लिए सफाई हो जाते हैं तथा ये जनाधिकार के सूचक हैं। भारत में प्रतिवेदी झाकाल, भूखमरी, बाढ़, झुसा, महामरी आदि का प्रकौप कियी ना कियी भाग में रहता ही है जिसमें हजारों व्यक्तियों की मृत्यु होती है। ये प्राकृतिक प्रकौप भारत में जनाधिकार के सूचक हैं।

(6) बढ़ी हुई बेकारी (Increasing unemployment):— भारत में लगातार बढ़ती हुई बेकारी भी जनाधिकार का सबसे बड़ा प्रमाण है। भारत में 1955-56 ई में करीब 53 लाख ०५ कित्त बेरोजगार थे जिनकी खरेद्या बढ़कर 2006-07 में करीब 361 लाख हो गयी। अबॉ स्मरणीय है कि पंचवर्षीय औजनाओं में रोजगार के अपसरी में लगातार वृद्धि

Page (5)

होने के बावजूद देश में जनाधिकरण का बहुतक है। भारत में जनाधिकरण

का बहुतक है।

(1) प्रति लाखित आय में घटी गति से सहित — भारत में प्रति लाखित आय में जनाधिकरण के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में जिस गति से छहिं औजनाओं के करोड़स्वरूप राष्ट्रीय आय में छहिं नहीं हुई है जो करोड़ हुई है यह गति से प्रति लाखित आय में छहिं नहीं हुई है जो करोड़ हुई है। उदाहरण के लिए 1950-51 में प्रति लाखित आय 8.812 करोड़ रुपये हो जायी तभा प्रति लिए इलाजों पर राष्ट्रीय आय 8.812 करोड़ रुपये हो जायी। वर्ष 2009-10 में बदल क्रमशः 54,39557 प्रति लाखित आय 246 करोड़ रुपये हो जायी। इस प्रकार जबकि करोड़ रुपये से 46,192 करोड़ रुपये हो जायी। इस प्रकार जबकि इस अवधि में राष्ट्रीय आय में 617 गुणी बढ़ि हुई, प्रति लाखित आय में केवल 188 गुणी बढ़ि हुई। यह देश में जनसंख्या बढ़ी से नहीं बढ़ी तो राष्ट्रीय आय में बढ़ि के अनुरूप ही कीव कीव जनाधिकरण आय में बढ़ि होती। इस प्रकार प्रति लाखित आय में बढ़ि होती। इस प्रकार प्रति लाखित आय में घटी गति से छहिं देश में जनाधिकरण का परिवारक है।

(2) निम्न जीवन स्तर !— भारत में देशवासियों का निम्न जीवन स्तर भी देश में जनाधिकरण का बहुत बड़ा प्रमाण है। यहाँ लोगों की प्रति लाखित आय अन्य देशों की तुलना में काफी कम है जिससे अक्षर रहन सहन का स्तर भी निम्न कोटि का है। उदाहरण के लिए 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति लाखित औसत राष्ट्रीय आय 47,930 डालर, जटिलियों में 46.040 डालर तभा जो प्रति लाखित भी जपकि भारत में यह केवल 1040 डालर भी। इस प्रकार प्रति लाखित कम राष्ट्रीय आय तभा लोगों का निम्न जीवन स्तर भारत में जनाधिकरण का परिवारक है।

निष्कर्ष:— हम भारत में जनाधिकरण के पहले सब विपक्ष में किये गये तर्कों को केवल बुके हैं। स्पष्ट है कि जनाधिकरण के विरोध में किये जाने वाले तर्कों में सत्यता नहीं है। अतः यह कहना जालत होगा कि भारत में जनाधिकरण की स्थिति नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में निष्कर्ष ही जनाधिकरण के इष्टजीवनी विधमान है। अब देश की जो स्थिति है तभा जिस हद तक हमें अपने साधनों का विकास कर चुके हैं, उस हालत में जनाधिकरण की समस्या वर्तमान है। वास्तव में जनाधिकरण आदर्श जनसंख्या तभा अन्तर्गत संस्थानों की धारणाएँ स्थिर नहीं बरन अस्तित्व गतिशील है। स्वाक्षर आदि में परिवर्तन के साथ इन धरणों में भी परिवर्तन हो सकता है।

The End

N.P. Ram
24/4/20